traffic on 2-2-1964. The estimated cost of the bridge is Rs. 123 lakhs approximately. The actual cost has not been worked out yet.

Broad gauge Line from Siliguri to Jogighopa

1214. **Shri P. C. Borooah:**
Shri Basumatari:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 86 on the 19th November, 1963 and state:

(a) the further progress made in laying the broad gauge line from Siliguri to Jogighopa; and

(b) when it is expected to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) and (b). The sub-grade works, both earthwork and bridges, on the Project are progressing according to schedule. The steel girders required for the bridges have also been arranged. Efforts are being made to establish the link for freight traffic by the end of 1965.

रेल यात्रा में सुधार

१२१५. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित हुआ है कि पैसेंजर गाड़ियों के धीरे चलने और उनकी अपर्याप्त संख्या के कारण सड़क द्वारा यात्रा अधिकाधिक बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड रेलों द्वारा यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए कोई उपाय करने का विचार कर रहा है ताकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसे उपायों को क्रियान्वित किया जा सके;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि सड़क परिवहन से रेलवे की आय कम हो रही है और उससे चुंगी तथा करों के अपवंचन में भी मदद मिलती है ; और

(घ) यात्री और माल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने और नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा क्या कार्रवाई करने का विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी) : (क) हाल के वर्षों में सड़क परिवहन द्वारा ढोये गये यात्री यातायात में कुछ वृद्धि हुई है । लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह वृद्धि सवारी गाड़ियों की धीमी रफ्तार या उनकी अपर्याप्त संख्या के कारण ही हुई हो । पंचवर्षीय आयोजनाओं के सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार के यातायात के परिवहन के लिए उपलब्ध साधनों के अन्दर ही रेल परिवहन क्षमता का विकास किया गया है ।

(ख) कोई विस्तृत आयोजना बनाने का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि राष्ट्र की चौथी आयोजना का आकार-प्रकार अभी निश्चित नहीं हुआ है, जिस पर रेलों की परिवहन योजना भी निर्भर है ।

(ग) दूसरे देशों की तरह इस देश में भी ऊंची दर वाले कुछ यातायात का परिवहन रेलों की बजाय सड़क के रास्ते होने लगा है । यह विशेष रूप से सड़क परिवहन के कुछ स्वाभाविक लाभ और रेलों की भाड़ा-दर व्यवस्था के कारण है । इससे रेलों की आमदनी पर कुछ हद तक बुरा असर पड़ता है । राष्ट्रीय परिवहन की एक उपयुक्त और दीर्घकालीन नीति निर्धारित करने और रेल-सड़क व्यवस्था में समन्वय रखने के लिए सर्वोत्तम तंत्र के विकास के सवाल पर परिवहन नीति और समन्वय सम्बन्धी एक उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है । इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। सड़क परिवहन परिचालकों द्वारा चुंगी और

दूसरे करों से बच निकलने के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) तीसरी आयोजना में यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था की गयी है उसका आधार यह है कि दूसरी आयोजना के अन्त में जितनी सीटें उपलब्ध थीं उनसे १५ प्रतिशत अधिक सीटें बढ़ायी जायें। उपलब्ध साधनों के भीतर चालु आयोजना अवधि विभिन्न खण्डों पर उत्तरोत्तर गाड़ियों की संख्या बढ़ायी जा रही है ।

जहां तक माल गाड़ियों का सवाल है, इसके लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था प्रारम्भिक यातायात पर आधारित है, जो तीसरी आयोजना के अन्त तक २४५२ लाख मीटरिक टन तक पहुंच जायेगा । तीसरी आयोजना में २४०० किलोमीटर लम्बी लाइनें बनाने की व्यवस्था है ।

गेहूं का आयात

१२१६. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में अन्य देशों से कितना गेहूं आयात किया गया और किन किन देशों से ;

(ख) देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश के भीतर की उपज और आयात किये गये खाद्यान्नों को मिला कर कितनी कमी पड़ी और उसे कैसे पूरा किया जा रहा है ; और

(ग) गेहूं का भाव कम कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) अप्रैल, १९६३ से फरवरी, १९६४ की अवधि में आयात की गयी मात्रा लगभग ३८.०२ लाख मीट्रिक टन थी ।

जिन देशों से गेहूं का आयात किया गया वे संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया और कनाडा हैं ।

(ख) खाद्यान्नों का आयात उपभोग की वर्तमान आवश्यकताएं पूरी करने और समीकरण भण्डार तैयार करने के लिए किया जाता है । सरकार का अनुमान है कि ये आयात इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होंगे ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी डिपो से उचित मूल्यों पर आयातित गेहूं की बहुत अधिक मात्रा देश भर में बहुत बड़ी संख्या में उचित मूल्य की दूकानों के द्वारा वितरण करने के लिए, दी जा रही है । अधिक से अधिक मात्रा में गेहूं के पदार्थ बनाने के लिए बेलन आटा मिलों को भी गेहूं दी जा रही है । गेहूं से बने पदार्थों के मिलों से निकासी के भाव अधिनियमित रूप से निर्धारित किए जाते हैं ।

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में मनीआर्डर फार्मों की कमी

१२१७. श्री विश्राम प्रसाद: क्या डाक तथा तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के डाकघरों में मनीआर्डर फार्मों और 'एकनालेजमेंट ड्यू' फार्मों की निरन्तर कमी रहती है जिससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कठिनाई कब तक दूर होगी?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।